यूएस-तालिबान संधि

लेखक- शुभाजीत रॉय (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

02 मार्च, 2020

"हाल ही में भारत की मौजूदगी में अमेरिका और तालिबान ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अफगान सरकार और भारत के लिए तालिबान और गनी शासन के साथ घनिष्ठ समीकरण को देखते हुए, इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं?"

शनिवार को, अमेरिका और तालिबान ने "अफगानिस्तान में शांति लाने" के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अगले 14 महीनों में अमेरिका और नाटो को सेना वापस लेने में सक्षम बनाएगा। भारत ने दोहा में हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया और कतर में राजदूत पी. कुमारन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।

यह समझौता तालिबान (अफगानिस्तान के "इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं) और अमेरिका के बीच हुआ है।" चार पन्नों के इस समझौते पर जाल्मे खलीलजाद, जो अफगानिस्तान सुलह के लिए विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि हैं और तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

अलग से, अफगान सरकार (इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान) और अमेरिका के बीच तीन पृष्ठ की संयुक्त घोषणा काबुल में जारी की गई।

प्रमुख तथ्य

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि लॉरेल मिलर ने अमेरिका-तालिबान सौदे में निम्नलिखित तथ्यों को इंगित किया है:-

सैनिकों की वापसी (TROOPS WITHDRAWAL): अमेरिका 135 दिनों में 8,600 सैनिकों को आनुपातिक रूप से और एक साथ वापस बुलाएगा, साथ ही नाटो या गठबंधन सेना की संख्या को भी वापस बुलाया जाएगा। इसके अलावा, सभी सैनिक 14 महीने के भीतर वापस बुला लिए जाएंगे, जिसमें सभी "गैर-राजनयिक नागरिक कर्मचारी" भी शामिल होंगे (अर्थात "खुफिया" कर्मी)।

तालिबान की प्रतिबद्धता (TALIBAN COMMITMENT): तालिबान द्वारा मुख्य आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता यह है कि तालिबान अपने किसी भी सदस्य, अन्य व्यक्ति या समूह को, जिसमें अल-कायदा भी शामिल है, अफगानिस्तान की मिट्टी का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं करेगा।

हालाँकि, जहाँ एक तरफ मिलर ने कहा है कि अल-कायदा का संदर्भ महत्त्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ यह संधि अन्य आतंकवादी समूहों, जैसे भारत-विरोधी समूह लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद, पर चुप है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत, अमेरिका का सहयोगी नहीं है और वह इस संधि के अंतर्गत नहीं आता है।

प्रतिबंध हटाना (SANCTIONS REMOVAL): तालिबान नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को तीन महीने (29 मई तक) और अमेरिकी प्रतिबंधों को 27 अगस्त तक हटा दिया जाएगा। इंट्रा-अफगान वार्ता में प्रगति होने से पहले प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा।

कैदियों की रिहाई (PRISONER RELEASE): मिलर ने इसे "परेशान करने वाला संभावित मुद्दा" के रूप में बताया है, क्योंकि अमेरिका-तालिबान समझौता और संयुक्त घोषणा अलग है और यह स्पष्ट नहीं है कि अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार "तालिबान को दी गयी छूट" के साथ है भी या नहीं?"

संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि अमेरिका विश्वास निर्माण उपायों पर तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण कैदियों को रिहा करने की व्यवहार्यता का निर्धारण करना शामिल है। जहाँ संयुक्त घोषणा में कोई संख्या या समय सीमा की बात नहीं कही गयी है, वहीं यूएस-तालिबान संधि में कहा गया है कि तालिबान के

5,000 कैदियों और तालिबान द्वारा पकड़े गये दूसरे पक्ष के 1,000 कैदियों को "10 मार्च (ओस्लो में इंट्रा-अफगान बातचीत शुरू होने वाली संभावित तारीख) तक" छोड़ दिया जाएगा।

संघर्ष विराम (CEASEFIRE): एक अन्य "परेशान करने वाला संभावित मुद्दा" संघर्ष विराम है। समझौते के अनुसार युद्ध विराम का मुद्दा तब शामिल किया जाएगा जब इंट्रा-अफगान वार्ता शुरू होगी और यह इंगित करता है कि वास्तविक युद्धविराम अफगान राजनीतिक समझौते के पूरा होने के साथ ही आएगा।

आगे की चुनौतियाँ

संयुक्त घोषणा अफगानिस्तान सरकार के लिए एक प्रतीकात्मक प्रतिबद्धता है। तालिबान को वह मिल गया है जो वे चाहते थे: सैनिकों की वापसी, प्रतिबंध हटाना, कैदियों की रिहाई। इसने पाकिस्तान, जो तालिबान का समर्थक है, को भी मजबूत किया है और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का प्रभाव इससे बढ़ेगा।

अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता के दौरान अफगान सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। अफगानिस्तान के लोगों का भविष्य अनिश्चित है और साथ ही साथ यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि तालिबान अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान कैसे करता है और क्या यह 1996-2001 के शासन के मध्ययुगीन प्रथाओं पर पुन: वापस जाएगा।

यह शांति की दिशा में पहला कदम है। अफगानिस्तान में शांति अब इस बात पर आधारित होगी कि कैसे अफगान बाहरी दबावों से स्वतंत्र होकर एक-दूसरे से बात करते हैं। 1989, 1992, 1996 और 2001 की तरह, पाकिस्तान के पास रचनात्मक भूमिका निभाने का अवसर है।

भारत और तालिबान

नई दिल्ली के लिए भी यह एक कठिन काम है। मुल्ला बरादर ने शांति प्रक्रिया का समर्थन करने वाले देशों में भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रदान की गई "सहायता" के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया।

भारत और तालिबान के बीच अतीत कड़वा रहा है। भारत, नई दिल्ली 1999 में IC-814 विमान अपहरण की कड़वी यादों को नहीं भुला है, जहाँ उसे आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था - जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था, जिसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जिसने पठानकोट (2016) और पुलवामा (2019) के साथ-साथ संसद (2001) पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। तालिबान ने हमेशा भारत को एक शत्रुतापूर्ण देश माना है, क्योंकि भारत ने 1990 के दशक में तालिबान विरोधी उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया था।

भारत ने तालिबान को कभी राजनयिक और आधिकारिक मान्यता नहीं दी। हाल के वर्षों में, जैसा कि यूएस-तालिबान वार्ता ने गति पकड़ी है, नई दिल्ली सभी हितधारकों के साथ संपर्क में है। लेकिन इसकी विदेश नीति की स्थापना सीधे तालिबान के साथ उलझने से बच गई। यहाँ तक कि जब अफगानिस्तान में पूर्व दूत अमर सिन्हा और पाकिस्तान में पूर्व दूत टीसीए राघवन को नवंबर 2017 में मास्को में तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए एक "गैर-आधिकारिक प्रतिनिधि" के रूप में भेजा गया था, तो ये एक "पर्यवेक्षक" के रूप में गए थे और प्रत्यक्ष वार्ता में शामिल नहीं हुए थे।

नई दिल्ली और काबुल

भारत ने हमेशा गनी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया है और गनी को उनकी जीत पर बधाई देने वाले बहुत कम देशों में शामिल था। गनी के साथ भारत की निकटता भी पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के उनके साझा दृष्टिकोण से आकर्षित हुई है। सरकार ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को शुक्रवार को काबुल भेजा, जिन्होंने शनिवार को गनी और वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व के साथ बैठक की और दोहा में यूएस-तालिबान समारोह के लिए अपना दूत भेजा था।

बैठक में श्रृंगला ने एक "स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक, बहुलवादी और समावेशी" अफगानिस्तान के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के हित संरक्षित हैं। उन्होंने "स्थायी और समावेशी" शांति और सामंजस्य के लिए भारत के समर्थन से भी अवगत कराया जो कि "अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित" है।

भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए, भारतीय विकास सहायता के साथ बामियान और मजार-ए-शरीफ प्रांतों में सड़क परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए है।

हालाँकि, कई भारतीय राजनयिकों का कहना है कि तालिबान के शीर्ष नेताओं के साथ औपचारिक संपर्क नहीं हुआ है, फिर भी भारत ने लगभग 3 बिलियन डॉलर की सामुदायिक विकास परियोजनाओं के माध्यम से पूरे अफगानिस्तान में पश्तून समुदाय तक पहुँच बना ली है। इन उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के कारण, राजनयिकों को लगता है कि भारत ने सामान्य अफगानों के बीच सद्भावना प्राप्त की है, जिनमें से अधिकांश पश्तून हैं और कुछ को तालिबान के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

इसलिए, भले ही पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगी तालिबान काबुल के सत्ता हलकों में प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन साउथ ब्लॉक के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नई दिल्ली के लिए यह सब चिंता का विषय नहीं है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में, अमेरिका-तालिबान द्वारा शांति संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इसके संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह समझौता भारत की गैर मौजूदगी में संपन्न हुआ।
2. इस संधि के तहत् केवल अमेरिकी सैनिक वापस बुलाए जाएंगे।
3. इस संधि के तहत् तालिबान, अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा को क्षति नहीं पहुँचाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) केवल 3 (d) 1 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Recently, a peace treaty was signed by the US-Taliban. Consider the following statements in this context:

1. This agreement was signed in the absence of India.
2. Under this treaty only American soldiers will be withdrawn.
3. Under this treaty, the Taliban will not harm the security of America and its allies.

Which of the above statements is/are correct ?

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) Only 3 (d) 1 and 3

नोट : 29 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. अमेरिका-तालिबान ऐतिहासिक शांति समझौता भारत के लिए एशिया में शक्ति संतुलन को स्थापित करने की संभावनाओं को प्रबल करता है। इस संदर्भ में भारत के समक्ष अवसर और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

The US-Taliban historical Peace Treaty reinforces India's prospects of establishing a balance of power in Asia. In this context, discuss the opportunities and challenges infront of India. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।